भारत का संघ और अन्य बनाम कमलजीत सिंह

(संदीप मौदगिल, जे.)

संदीप मौदगिल से पहले**,** जे**.**

भारत का संघ और अन्य-अपीलार्थी

बनाम

2017 का प्रतिवादी एल. पी. ए. संख्या 2359 (ओ एंड एम) कमलजीत सिंह

26 अगस्त, 2022

भारत का संविधान**, 1950**-अनुच्छेद **51**-केंद्रीय पुलिस रिजर्व बल नियम**, 1955,** आर**.** एल**. 29 (**डी**)**-लेटर पेटेंट अपील-अधिकारी की तीन वार्षिक वेतनवृद्धि बंद कर दी गई डी**.** आई**.** जी**.** पी**. (**सी**.** आर**.** पी**.** एफ**.)** ने उन्हें सेवा से और बर्खास्त कर दिया-अपील और पुनरीक्षण ने **2013** के सी**.** डब्ल्यू**.** पी**. 20155** में सिंह पीठ को **रद** कर दिया और सजा के आदेशों को **रद** कर दिया-आदेशों में जांच रिपोर्ट के बारे में विस्तार से नहीं बताया गया-प्रारंभिक रुख पर जारी किया गया कारण बताएँ नोटिस दो कर्मियों के लिए था**,** लेकिन बर्खास्तगी के आदेश **4** सिपाहियों के खिलाफ थे-आयोजित**,** पुनरीक्षण प्राधिकरण द्वारा पारित आदेश गैर-बोलने वाले आदेश थे-जब गंभीर परिणाम के ऐसे आदेश पारित किए जाते हैं**,** तो बर्खास्तगी की चरम सजा लगाते समय सभी मुद्दों से निपटने के लिए एक सुविचारित आदेश पर विचार किया जाना चाहिए।एकल न्यायाधीश के आदेशों को बरकरार रखा गया-वर्तमान अपील **रद** कर दी गई।

यह अभिनिर्धारित किया गया कि यद्यपि हम भारत संघ के वकील से सहमत हैं कि पुनरीक्षण की शक्तियों का प्रयोग अपीलीय प्राधिकरण द्वारा किया जा सकता था, यद्यपि वर्तमान मामले में विलंबित चरण में किया गया है, हमारी यह सुविचारित राय है कि विद्वान एकल न्यायाधीश द्वारा दिए गए कारण कि उक्त शक्ति उपलब्ध नहीं थी, नियम 29 (घ) के प्रावधानों को देखते हुए टिकाऊ नहीं माना जा सकता है जैसा कि ऊपर पुनः प्रस्तुत किया गया है।

(पैरा 25)

आगे अभिनिर्धारित किया कि कमांडेंट द्वारा 01.08.2009 पर विधिवत व्यक्त किया गया विवादित आदेश, अपील को **रद** करना उचित नहीं था और इसे कायम नहीं रखा जा सकता है। इसी तरह, दिनांक 23.04.2010 (अनुलग्नक पी-12) 07.05.2013 (अनुलग्नक पी-16) की अपील में बाद का आदेश भी न्यायिक जांच की कसौटी पर खरा नहीं उतर सकता है और तदनुसार, हम यहां ऊपर देखे गए कारणों के लिए विद्वान एकल न्यायाधीश के आदेश में कोई गलती नहीं पाते हैं।

(पैरा 26)

शिवॉय धीर, अपीलार्थियों यू. ओ. आई. के लिए वरिष्ठ पैनल वकील।

प्रतिवादी की ओर से अधिवक्ता राजीव आनंद ने कहा।

जी. एस. संधवालिया, जे.

(1) भारत संघ के **उदाहरण** पर वर्तमान पत्र पेटेंट अपील में विचार रिट याचिकाकर्ता को विद्वान एकल न्यायाधीश द्वारा दी गई राहत के बारे में है, जिसके तहत पुलिस उप महानिरीक्षक (डी. आई. जी. पी.), **केन्द्रीय रिर्जव पुलिस**, चंडीगढ़ द्वारा पारित दिनांक 15.06.2009 (पी-10) का आदेश, जिसने 25.02.2009 (अनुलग्नक पी-7) पर जारी कारण बताओ नोटिस के अनुसरण में सजा को संचयी प्रभाव से तीन वार्षिक वेतन वृद्धि सेवन से बढ़ाकर सेवा से बर्खास्त कर दिया था। 23.04.2010 (अनुलग्नक पी-12) पर अपील को रद करने और विशेष महानिदेशक, **केन्द्रीय रिर्जव पुलिस**, जम्मू और कश्मीर क्षेत्र द्वारा 07.05.2013 (अनुलग्नक पी-16) पर संशोधन को खारिज करने वाले अपील के आदेशों को भी 17.08.2017 पर 2013 के **सी.डब्ल्यू.पी. संख्या** 20155 में रद कर दिया गया था।

(2) विद्वान एकल न्यायाधीश द्वारा दिया गया तर्क यह था कि अपीलीय प्राधिकरण के पास केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल नियम, 1955 (इसके बाद '1955 नियम' के रूप में संदर्भित) के नियम 28 के तहत दंड बढ़ाने की कोई शक्ति नहीं है और केवल नियम 29 (डी) के तहत शक्ति संशोधन की है। इसलिए, एक निष्कर्ष दर्ज किया गया कि अपीलीय प्राधिकरण ने अपील पर विचार करते समय नियम 28 के तहत अपनी शक्ति को सीमित करने के बजाय पुनरीक्षण प्रावधान को लागू करने में अपने अधिकार क्षेत्र को पार कर लिया था।तदनुसार, यह अभिनिर्धारित किया गया कि पुनरीक्षण प्राधिकरण ने इसके बाद अमान्य आदेश की पुष्टि की थी और इसलिए, रिट याचिकाकर्ता को 3 सप्ताह की अवधि के भीतर बहाल करने और वेतन अवशिष्ट की गणना करने और 3 महीने की अवधि के भीतर उसे वितरित करने के निर्देश दिए गए थे।

(3) भारत संघ के वकील ने, तदनुसार, 1955 के नियमों की धारा 29 (डी) के प्रावधानों को यह प्रस्तुत करने के लिए संदर्भित किया है कि डी. आई. जी. किसी भी सजा के पुरस्कार के रिकॉर्ड की मांग कर सकता है और उसे बढ़ा सकता है। तदनुसार, यह प्रस्तुत किया जाता है कि प्रावधान के अनुसार मौखिक या लिखित रूप से एक अवसर दिया जाना था कि सजा क्यों नहीं बढ़ाई जानी चाहिए और उक्त प्रक्रिया का पालन किया गया था। इसलिए, विद्वान एकल न्यायाधीश का आदेश इस हद तक टिकाऊ नहीं था कि यह निष्कर्ष दर्ज किया गया है कि अपीलीय प्राधिकरण के पास सजा बढ़ाने की शक्ति नहीं थी।तदनुसार, यह इंगित किया गया है कि चूंकि अपील डी. आई. जी. (पी) के समक्ष लंबित थी, इसलिए उन्हें 1955 के नियमों के नियम 29 (डी) के तहत शक्ति का प्रयोग करने के लिए उचित ठहराया गया था और विवादित आदेश एक दुर्बलता से ग्रस्त था, क्योंकि नियम के प्रावधानों को सही ढंग से ध्यान में नहीं रखा गया है।

(4) श्री राजीव आनंद, भारत का संघ और अन्य बनाम कमलजीत सिंह पर प्रतिवादी के वकील दूसरी ओर प्रस्तुत किया गया है कि डी. आई. जी. पी. द्वारा किसी भी समय पुनरीक्षण शक्ति का प्रयोग अपने स्वयं के प्रस्ताव पर नहीं किया जा सकता है न कि सजा के आदेश के खिलाफ दायर अपील पर जो शुरू में लगाया गया था।यह बताया गया कि तीन वार्षिक वेतन वृद्धि को रोकने के खिलाफ बार-बार अभ्यावेदन दायर किए गए थे और अपीलीय प्राधिकरण नियम 29 (डी) के प्रावधानों को लागू करने के लिए अपनी नींद से जाग गया था। यह प्रस्तुत किया गया कि अनुशासनात्मक प्राधिकरण ने देखा कि घटना के तरीके के बारे में विवाद था और इस निष्कर्ष पर पहुंचा था कि वरिष्ठ अधिकारी का बयान स्वीकार करने योग्य नहीं था और चिकित्सा रिकॉर्ड में कुछ हेरफेर किया गया था और उक्त अधिकारी के बयानों में विरोधाभास था, जिन्होंने कंपनी के कर्मियों के खिलाफ असंसदीय भाषा का इस्तेमाल किया था।इसलिए, संचयी प्रभाव और इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए कि अपीलकर्ता कम उम्र का था और इस तथ्य को भी ध्यान में रखते हुए कि वरिष्ठ अधिकारी द्वारा असंसदीय भाषा का उपयोग किया गया था, तीन वार्षिक वेतन वृद्धि पर रोक घटना के संबंध में थी और सेवा से बर्खास्तगी का चरम आदेश डी. आई. जी. द्वारा गलत तरीके से पारित किया गया था।

(5) यह आगे प्रस्तुत किया गया कि यह एक ऐसा मामला था जिसमें रिट याचिकाकर्ता को बर्खास्तगी का आदेश पारित होने तक पहले ही एक वृद्धि का नुकसान हो चुका था और साथ ही पेंशन, वार्षिक वृद्धि और छुट्टी की गणना के लिए आई. डी. 1 से आई. डी. 2 तक के निलंबन की अवधि को भी नहीं गिना जाना था, जो इस मुद्दे के अनुरूप था और उक्त तथ्यों की अपीलीय प्राधिकरण द्वारा ठीक से जांच नहीं की गई है, जिसने अपील दायर करने और दिए गए अभ्यावेदन से पहले अपनी पुनरीक्षण शक्ति का प्रयोग नहीं करने का विकल्प चुना था।यह आगे तर्क दिया गया कि 1955 के नियमों के नियम 28 के तहत सजा को संशोधित करने की कोई शक्ति नहीं थी।

(6) पेपर-बुक के अवलोकन से पता चलता है कि रिट याचिकाकर्ता को पिंजौर में 07.09.2001 पर केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल (जिसे इसके बाद 'सीआरपीएफ' कहा जाता है) में एक कांस्टेबल के रूप में सूचीबद्ध किया गया था और उसे बल No.015234644 आवंटित किया गया था। नीमच (मध्य प्रदेश) में अपना प्रारंभिक प्रशिक्षण पूरा करने के बाद, उन्हें 84 बटालियन सीआरपीएफ में तैनात किया गया था। उत्तर प्रदेश में चुनाव कर्तव्यों के लिए कंपनी 'डी' के साथ तैनात होने के दौरान, जिला सुल्तानपुर के विनोबा भावे इंटर कॉलेज प्रेम नगर में रहने के दौरान सहायक कमांडेंट के साथ दुर्व्यवहार, हाथापाई की घटना हुई।रिट याचिकाकर्ता और तीन अन्य को 15.06.2007 से निलंबित कर दिया गया था और उनके विरूद्ध निम्नलिखित आरोप-पत्र जारी किया गया था:

"अनुच्छेद-**1**

कि इस बटालियन के निम्नलिखित नामित कर्मियों ने फोर्स के सदस्य होने के नाते कांस्टेबल के रूप में काम करते हुए आदेशों की अवज्ञा और कर्तव्य के प्रति समर्पण की कमी और अन्य कदाचार, दुर्व्यवहार जिसमें दुर्व्यवहार और श्री के साथ हाथापाई शामिल है, के रूप में काम किया। दया राम सांडे सहायक। कॉमडेट। (आई. आर. एल. ए.-5608) अपने आवास पर 22-5-07 पर जब डी/84 बी. एन. विनोबा भावे इंटर कॉलेज प्रेम नगर जिले में ठहरे हुए थे। 2007 के यूपी आम चुनाव के दौरान सुल्तानपुर यूपी जो केन्द्रीय रिर्जव पुलिस अधिनियम 1949 की धारा 11 (1) के तहत एक दंडनीय अपराध है।

1. 015234644 सिपाही/जीडी कमलजीत सिंह

2. 005230191 सिपाही/जी. डी सतीश कुमार

3. 941445206 सिपाही/जी. डी. मो. अमीन वाणी

4. 015281018 सिपाही/जी. डी. मलखान सिंह "

(7) सुरेन्द्र कुमार, द्वितीय कमान, जिन्हें जाँच अधिकारी के रूप में नियुक्त किया गया था, ने अपनी रिपोर्ट दिनांक 29.06.2007 दी थी, जिस प्रकृति में कमी पाई ग ई और उसे रद्द कर दिया गया और 14.11.2007 को डीनोवो जाँच के आदेश पारित किए गए। परिणामस्वरूप, जांच रिपोर्ट (अनुलग्नक पी-2) प्रस्तुत की गई जिसमें चार अपर ाधी सिपाहियों के खिलाफ आरोप साबित किए गए।

(8) रिट याचिकाकर्ता ने 08.05.2008 (अनुलग्नक पी-2) को उक्त रिपोर्ट पर अपनी आपत्तियां प्रस्तुत कीं, जिसमें अनुशासनात्मक प्राधिकारी, द्वितीय कमान ने उक्त जांच की विस्तार से जांच की। दिनांक 05.06.2008 (अनुलग्नक पी-3) के कार्यालय आदेश के माध्यम से वह इस निष्कर्ष पर पहुंचे कि 'डी' कंपनी विनोबा भावे इंटर कॉलेज, प्रेम नगर, जिला सुल्तानपुर में प्रातः 10:30 बजे 22.05.2007 पर ड्यूटी के लिए पहुंची थी। जहाँ ठहरने की व्यवस्था की गई है। छात्रों की परीक्षा चल रही थी और कंपनी को बाहर आंगन में इंतजार करना पड़ा।हालांकि, कंपनी के कर्मियों ने अंदर जाना शुरू कर दिया था और सहायक कमांडेंट ने आपत्ति जताई और कर्मियों को अंदर जाने के लिए डांट लगाई और उन्हें अंदर आने के लिए कहा।उन्होंने स्पष्ट रूप से असंसदीय भाषा का उपयोग करके पूरी कंपनी को गाली दी थी और फिर कंपनी के कर्मियों को 45 मिनट तक चिलचिलाती धूप में खड़ा रखा था।रिट याचिकाकर्ता जो एक अन्य पलटन के साथ जुड़ा हुआ था, उसे व्यवस्थित कमरे में उपस्थित

होने के लिए कहा गया था।सहायक कमांडेंट के एस. पी., फतेहपुर के कार्यालय में बैठक में भाग लेने के बाद, वह रात में लौट आए थे और अपने कमरे में गए थे। कॉलेज रात 10:00 बजे 40-50 कर्मी सुबह दूसरों को दिए गए दुव्यवहार के बारे में उनसे बात करने के लिए उनके कमरे के बाहर जमा हुए थे। (9) यह देखा गया कि इसकी पुष्टि नहीं की जा सकी कि चार आरोपित कर्मियों द्वारा सहायक कमांडेंट के साथ कोई हाथापाई की गई थी या नहीं और एच. सी. प्रेम लाल शर्मा के बयान को संदिग्ध और आत्म-विरोधाभासी माना गया।हालाँकि, यह देखा गया कि उक्त गवाह ने स्वीकार किया था कि यह घटना सहायक कमांडेंट द्वारा इस्तेमाल किए गए भद्दे शब्दों और गालियों के कारण हुई थी।यह भी देखा गया कि रिट याचिकाकर्ता ने उक्त घटना के बाद अपने हथियारों के साथ संवेदनशील गुर्जर आरक्षण आंदोलन के कारण उक्त वरिष्ठ अधिकारी को 7-8 दिनों के लिए संरक्षित किया था और इस प्रकार, यह उपरोक्त अधिकारी के साथ व्यक्तिगत संबंधों को दर्शाता है । उक्त वरिष्ठ अधिकारी द्वारा प्रस्तुत चिकित्सा रिपोर्ट में हेरफेर किया गया था और एक साधारण कागज के टुकड़े पर तैयार किया गया था, जो संदिग्ध था और यह तथ्य कि अधिकारी ने खुद को 24.05.2007 पर जांचा था, लेकिन जो रिपोर्ट प्रस्तुत की गई थी वह 23.05.2007 पर बनाई गई थी और चिकित्सा अधिकारी को 22.05.2007 पर एक पत्र लिखा गया था।

(10) इस प्रकार, घटना की सच्चाई और यहां तक कि जयपुर के स्वाई मान सिंह होस्पिता से 08.06.2007 पर की गई एक्स-रे रिपोर्ट पर भी संदेह पैदा हो गया और रिपोर्ट यह थी कि सिर पर कोई चोट नहीं पाई गई थी और उनके दाहिने हाथ की तर्जनी पर मामूली सूजन और खरोंच पाई गई थी।इस प्रकार, एक निष्कर्ष दर्ज किया गया कि यह पता नहीं लगाया जा सका है कि संबंधित अधिकारी को 22.05.2007 पर घटना के दौरान चोट लगी है या नहीं।यह देखा गया कि कंपनी कमांडर कर्मियों के खिलाफ नियमों के तहत कार्रवाई करने में सक्षम था, लेकिन उसने अपनी गलती छिपाने की कोशिश की और कर्मियों के खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई करने में विफल रहा। इसलिए, एक निष्कर्ष पर पहुंचा गया कि अनुशासनात्मक प्राधिकरण उन आरोपों के संबंध में जांच अधिकारी की रिपोर्ट से सहमत नहीं था, जिन्हें किसी भी संदेह से परे साबित किया गया था।वही इस आधार पर था कि कोई चश्मदीद गवाह नहीं था जो यह साबित कर सके कि वरिष्ठ के साथ हाथापाई की गई थी और यह माना गया था कि केवल परिस्थितिजन्य सबूत थे और 40-50 कर्मी दिन के समय उनके द्वारा उपयोग किए गए भद्दे शब्दों के कारण वरिष्ठ के कमरे के बाहर इकट्ठा हुए थे।

(11) यह देखा गया कि वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा कर्मियों से बात करते समय असंसदीय भाषा का उपयोग नहीं करने के लिए विभिन्न संचारों को संबोधित किया गया था। इसलिए, उक्त तथ्य को ध्यान में रखते हुए संदेह का लाभ सिपाहियों की कम उम्र और इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए दिया गया था कि उनके परिवार प्रभावित होंगे और बेरोज़गारी का बोलबाला था इसलिए, 1955 के

नियमों के नियम 27 के साथ पठित केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल अधिनियम, 1949 (इसके बाद '1949 अधिनियम' के रूप में संदर्भित) की खंड 11 (1) के तहत शक्तियों का प्रयोग करते हुए, तीन सिपाहियों पर तीन साल के लिए वेतन वृद्धि पर रोक लगा दी गई थी, जबकि सिपाही मोहम्मद अमीन वाणी को 28 दिनों के लिए क्वार्टर गार्ड कारावास का दंड दिया गया था यानी 05.06.2008 से 02.07.2008 तक।उन पर लगाए गए संचयी प्रभाव के साथ तीन वेतन वृद्धि के ठहराव में उस अवधि के दौरान अर्जित वेतन वृद्धि शामिल थी जो भविष्य में देय नहीं होगी। निलंबन की अवधि को 15.06.2007 से 04.06.2008 माना जाना था और उस अवधि के दौरान उन्हें कोई अन्य वेतन और भत्ते देय नहीं होंगे।निलंबन की अवधि को पेंशन, वार्षिक वेतन वृद्धि और छुट्टी की गणना के लिए नहीं गिना जाना था।

(12) कमांडेंट द्वारा दी गई उक्त सजा से व्यथित होआदेश, रिट याचिकाकर्ता ने पुलिस उप महानिरीक्षक, सीआरपीएफ, चंडीगढ़ के समक्ष 30.06.2008 (अनुलग्नक पी-4) पर एक अपील दायर की कि यह उचित नहीं था और निलंबन की अवधि को आदेशतव्य अवधि के रूप में माना जाए ताकि उसे आर्थिक नुकसान से बचाया जा सके।एक अन्य संचार दिनांक 09.08.2008 (अनुलग्नक पी-5) को पुलिस महानिरीक्षक, सीआरपीएफ, चंडीगढ़ को संबोधित किया गया था, जिसमें पहले की अपील का संदर्भ दिया गया था।इसके बाद दायर की गई पिछली अपीलों का संदर्भ देते हुए पुलिस महानिरीक्षक को दायर की गई पिछली अपीलों पर निष्क्रियता के कारण 02.12.2008 (अनुलग्नक पी-6) पर संशोधन को प्राथमिकता दी गई।

(13) इस प्रकार, यह स्पष्ट होगा कि पुनरीक्षण प्राधिकरण ने उस अवधि तक नियम 29 (डी) के तहत अपनी शक्तियों का प्रयोग नहीं किया और कभी भी अभिलेख नहीं मांगे।नियम 29 (डी) के तहत परिभाषित पुनरीक्षण प्राधिकरण पुलिस उप महानिरीक्षक भी होगा जो नियम 28 के तहत अपीलीय प्राधिकरण भी था।1955 के नियमों का नियम 29 इस प्रकार हैः-

> “29. पुनरीक्षण।—(क) बल का एक सदस्य जिसकी अपील एक सक्षम प्राधिकारी द्वारा रद कर दी गई है, वह अगले वरिष्ठ प्राधिकरण में संशोधन के लिए याचिका दायर कर सकता है। पुनरीक्षण की शक्ति का प्रयोग केवल तभी किया जा सकता है जब कुछ भौतिक अनियमितताओं के परिणामस्वरूप, अन्याय हुआ हो या न्याय की हानि हुई हो या नए साक्ष्य का खुलासा किया गया हो।

(ख) नियम 28 के उप-नियम (ग) से (छ) के तहत अपील के लिए निर्धारित प्रक्रिया भारत का संघ और अन्य बनाम कमलजीत सिंह पर यथातचित परिवर्तनो सहित लागू होग'।

(ग) अगला वरिष्ठ प्राधिकारी पुनरीक्षण याचिका पर आदेश पारित करते समय अपने विवेक से सजा बढ़ा सकता है:बशर्ते कि सजा बढ़ाने से पहले अभियुक्त को यह कारण दिखाने का अवसर दिया जाएगा कि उसकी सजा क्यों नहीं बढ़ाई जानी चाहिए:

बशर्ते कि दंड को बढ़ाने वाला आदेश, अपील के उद्देश्य से, एक मूल आदेश के रूप में माना जाएगा, सिवाय इसके कि जब वह सरकार द्वारा पारित किया गया हो, जिस मामले में आगे कोई अपील नहीं होगी, और ऐसे आदेश के खिलाफ अपील होगी -

(i) महानिरीक्षक को, यदि यह उप महानिरीक्षक द्वारा पारित किया गया है; और

(ख) विशेष महानिदेशक या अतिरिक्त महानिदेशक प्रमुख क्षेत्र को, यदि यह महानिरीक्षक द्वारा पारित किया गया है; और

(ग) महानिदेशक को यदि यह विशेष महानिदेशक या अतिरिक्त महानिदेशक प्रमुख क्षेत्र द्वारा पारित किया गया है; और

(iii) केंद्र सरकार को, यदि इसे महानिदेशक द्वारा पारित किया गया है।]

(घ) महानिदेशक या विशेष महानिदेशक या क्षेत्र का नेतृत्व करने वाले अतिरिक्त महानिदेशक या महानिरीक्षक या उप महानिरीक्षक किसी भी सजा के दिए जाने के रिकॉर्ड मांग सकते हैं और इसकी पुष्टि, वृद्धि, संशोधन या वार्षिक रूप से कर सकते हैं, या ऐसे आदेश पारित करने से पहले आगे की जांच कर सकते हैं या निर्देश दे सकते हैं:

बशर्ते कि जिस मामले में सजा बढ़ाने का प्रस्ताव है, आरोपी को मौखिक या लिखित रूप से कारण बताने का अवसर दिया जाएगा कि उसकी सजा क्यों नहीं बढ़ाई जानी चाहिए।"

(14) जाहिर है 25.02.2009 (अनुलग्नक पी-7) पर इसके बाद रिट याचिकाकर्ता कमलजीत सिंह और अन्य सिपाही सतीश कुमार को एक कारण बताओ नोटिस जारी किया गया था कि 1955 के

नियमों के नियम 28 और 29 (डी) के तहत शक्ति का प्रयोग करते हुए सजा को सेवा से बर्खास्त करने के लिए क्यों नहीं बढ़ाया जाना चाहिए, इस तथ्य के कारण कि बल के समूह-ए राजपत्रित अधिकारी के साथ हाथापाई/हमला कर रहा था और इसलिए, उक्त व्यक्ति बल में बनाए रखने के योग्य नहीं थे। उक्त कारण बताओ नोटिस जारी करते समय अनुशासनात्मक जांच फाइल पर अभियोजन पक्ष के गवाहों के बयान का संदर्भ दिया गया था। (15) उक्त कारण बता ओ नोटिस का जवाब 14.03.2009 (अनुलग्नक पी-8) पर इस आधार पर दिया गया था कि कमांडेंट द्वारा लगाया गया जुर्माना उचित नहीं था क्योंकि यह संदेह का लाभ प्रदान नहीं करता था और अभियोजन पक्ष के गवाहों द्वारा आरोप साबित नहीं किए गए थे जैसा कि विभाग द्वारा प्रस्तुत किया गया था।

(16) अपीलीय प्राधिकरण ने दिनांक 15.06.2009 (अनुलग्नक पी-10) के आदेश के माध्यम से एक गैर- सपष्ट आदेश में सभी चार कर्मियों को सेवा से बर्खास्त करने का आदेश पारित किया।उक्त आदेश का कार्यात्मक भाग इस प्रकार हैः-

> "8. उपरोक्त कर्मियों द्वारा दिए गए कारण बताएँ नोटिस के जवाबों को देखने के बाद, मैंने पाया कि हालांकि वे निर्दोष होने का दावा करते हैं, लेकिन अपने दावे के समर्थन में कोई भी ठोस सबूत, नया तथ्य सामने लाने में विफल रहे। इसलिए, अधोहस्ताक्षरित व्यक्ति पूरी तरह से आश्वस्त है कि उपरोक्त कर्मियों को अनुशासनात्मक प्राधिकरण यानी कमांडेंट 84 बटालियन द्वारा सजा दी जाती है। सी. आर. पी. एफ. उपरोक्त कर्मियों द्वारा किए गए अपराध की गंभीरता को कर्तव्य के दौरान आपराधिक बल का उपयोग करने और अपने वरिष्ठ अधिकारी पर हमले की सीमा तक नहीं समझता है।इसने मेरी राय की पुष्टि की है कि सेवा में इन कर्मियो को सेवा मे बनाए रखना बल की अच्छी व्यवस्था और अनुशासन के लिए हानिकारक होगा।
>
> 9. इसलिए, सी. आर. पी. एफ. नियम, 1955 के नियम-28 के तहत अधोहस्ताक्षरित शक्तियों का प्रयोग करते हुए कमांडेंट 84 बटालियन द्वारा उन्हें दी गई सजा के खिलाफ संख्या 015234644 सी. टी./जी. ओ. कमलजीत सिंह और 84 बटालियन के 005130191 सी. टी./जी. डी. सतीश कुमार द्वारा दायर अपील को खारिज कर दिया जाता है। इसके अलावा, सी. आर. पी. एफ. नियम, 1955 के नियम 29 (डी) के तहत अधोहस्ताक्षरित शक्तियों का प्रयोग करते हुए 84 बटालियन यानी सी. टी./जी. डी. कमलजीत सिंह, 005130191 सी. टी./जी. डी. सतीश कुमार, 015281018 सी. टी./जी. डी. मलखान सिंह संख्या 1941445256 और सी. टी./जी. डी. मोहम्मद अमीन वानी के उपरोक्त सभी बल कर्मियों को "सेवा से बर्खास्त" करने की सजा दी जाती है। यह

आदेश उस तारीख से प्रभावी होगा जब इस आदेश की प्रति उपरोक्त कर्मियों को दी जाएगी।"

(17) यह ध्यान देना उचित है कि उक्त आदेश जांच रिपोर्ट के बारे में विस्तार से नहीं बताता है जैसा कि कमांडेंट द्वारा किया गया था, जिस पर उपरोक्त अनुच्छेद संख्या 8 से 11 में चर्चा की गई है। बल्कि अपीलीय प्राधिकरण अपनी पुनरीक्षण शक्तियों का प्रयोग करते हुए यह भी ध्यान देने में विफल रहा कि सिपाही मोहम्मद अमीन वानी को क्वार्टर गार्ड की सजा दी गई थी और इस प्रकार, बर्खास्तगी आदेश पारित करते समय इस तथ्य के कारण कि उनकी भूमिका अनुशासनात्मक प्राधिकरण द्वारा देखी गई तुलना में सीमित थी और इस प्रकार, उक्त अवधि से पहले ही गुजर चुकी होगी, लेकिन इसके बावजूद बर्खास्तगी के उक्त कर्मियों पर सजा का दूसरा आदेश लगाया।25.02.2009 पर जारी कारण दर्शाओ नोटिस से यह भी पता चलता है कि यह केवल दो कर्मियों के लिए था, लेकिन बर्खास्तगी का आदेश चार कांस्टेबलों के बारे में है।

(18) अन्यथा भी, हमारी यह सुविचारित राय है कि आदेश स्वयं निरर्थक है और पुनरीक्षण प्राधिकरण अनुशासनात्मक प्राधिकरण द्वारा पारित किए गए सुविचारित आदेश पर विचार करने में विफल रहा है। उसी ने सभी तथ्यों और जिस तरीके से घटना हुई थी और उक्त घटना की पृष्ठभूमि को ध्यान में रखा था और इस तथ्य के बावजूद कि इस तरह के वरिष्ठ अधिकारी ने असंसदीय भाषा का उपयोग करके कंपनी का दुरुपयोग किया था, इस तथ्य के बावजूद कि ऐसे निर्देश थे कि सिपाहियों को उक्त तरीके से संबोधित नहीं किया जाना था। रिट याचिकाकर्ता, जो उस समय लगभग 8 वर्ष की सेवा में था, को बर्खास्त करने की चरम सजा देते हुए पुनरीक्षण प्राधिकरण द्वारा इन पहलुओं पर कभी ध्यान नहीं दिया गया।

(19) यह स्थापित सिद्धांत है कि जब इस तरह के गंभीर परिणाम का आदेश पारित किया जाता है, तो उसे उन सभी मुद्दों से निपटना चाहिए था जो अनुशासनात्मक प्राधिकरण द्वारा उत्पन्न और नोटिस किए गए थे और जिन्हें अपीलीय प्राधिकरण द्वारा अपनी संशोधन की शक्ति का प्रयोग करते हुए और बर्खास्तगी की चरम सजा देते हुए रद कर दिया गया था। में पारित सर्वोच्च न्यायालय के फैसले का संदर्भ दिया जा सकता ह संभागीय वन अधिकारी**,** कोठागुडेम और अन्य बनाम मधुसूदन राव 1, जिसमें यह अभिनिर्धारित किया गया था कि समीक्षा प्राधिकरण संशोधन/अपील को अस्वीकार करते समय कारण बताएगा क्योंकि एक न्यायिक कार्य किया जा रहा है। उक्त मामले में,

सर्वोच्च न्यायालय उच्च न्यायालय की खण्ड पीठ के आदेश पर विचार कर रहा था जिसमें न्यायाधिकरण के आदेश को बरकरार रखा गया था जिसमें प्रतिवादी को सेवा में बहाल करने का निर्देश दिया गया था।तदनुसार, यह अभिनिर्धारित किया गया था कि यद्यपि एक आदेश 1 (2008) 3 एस. सी. सी. 469 पर सहमत होने और पुष्टि करने के लिए विस्तृत कारण नहीं दिए गए होंगे। अपीलीय प्राधिकारी द्वारा पारित किया गया, लेकिन अपर धी अधिकारी को अपील को खारिज करने के लिए कम से कम अपीलीय या पुनरीक्षण प्राधिकारी के मन को जानने का अधिकार है और यह सामने आना चाहिए।

(20) वर्तमान मामले में यह ध्यान देने योग्य है कि सजा को बढ़ाते समय आदेश के लिए कोई कारण नहीं दिए गए थे, इस तथ्य के अलावा कि जांच प्राधिकरण इस निष्कर्ष पर पहुंचा था कि आरोप साबित हो गए थे और वरिष्ठ अधिकारी पर हमला किया गया था, लेकिन इसके विपरीत कमांडेंट द्वारा उसी पर चर्चा की गई थी जो ऊपर देखा गया था। इस प्रकार, अपीलीय/पुनरीक्षण प्राधिकरण द्वारा कारण होने चाहिए थे कि दंड बढ़ाने से पहले कमांडेंट द्वारा दिया गया तर्क कैसे गलत था और इसलिए, यह सुरक्षित रूप से कहा जा सकता है कि दंड बढ़ाने का आदेश कारणों की अनुपस्थिति में से ग्रस्त है।

(21) शीर्ष के फैसले पर भी भरोसा किया जा सकता है। अदालत ने क्रांति एसोसिएट्स प्राइवेट लिमिटेड में पारित किया और अन्य बनाम मसूद अहमद खान और अन्य, जिसमें यह अभिनिर्धारित किया गया है कि प्रशासनिक आदेशों में भी कारण होने चाहिए, क्योंकि निर्णय व्यक्तियों को प्रतिकूल रूप से प्रभावित करता है। उक्त निर्णय में निम्नलिखित सिद्धांत निर्धारित किए गए थेः-

"47. उपरोक्त चर्चा का सारांश देते हुए, यह न्यायालय कहता हैः ए। भारत में न्यायिक प्रवृत्ति हमेशा कारणों को दर्ज करने की रही है, यहां तक कि प्रशासनिक निर्णयों में भी, अगर इस तरह के निर्णय किसी पर प्रतिकूल प्रभावित करते हैं।

बी- एक अर्ध-न्यायिक प्राधिकरण को अपने निष्कर्षों के समर्थन में कारणों को दर्ज करना चाहिए।

ग- कारणों को दर्ज करने पर जोर देना न्याय के व्यापक सिद्धांत को पूरा करने के लिए है कि न्याय न केवल किया जाना चाहिए, बल्कि किया गया भी प्रतीत होना चाहिए।

घ- कारणों को दर्ज करना न्यायिक और अर्ध-न्यायिक या यहां तक कि प्रशासनिक शक्ति के किसी भी संभावित मनमाने प्रयोग पर एक वैध प्रतिबंध के रूप में भी काम करता है।

ई- कारण आश्वस्त करते हैं कि निर्णय निर्माता द्वारा प्रासंगिक आधारों पर और बाहरी विचारों की अवहेलना करके विवेक का प्रयोग किया गया है।

च- निर्णय लेने की प्रक्रिया में कारण वस्तुतः उतने ही अपरिहार्य घटक बन गये हैं जितना कि न्यायिक, अर्ध-न्यायिक और यहां तक कि प्रशासनिक निकायों द्वारा प्राकृतिक न्याय के सिद्धान्तों का पालन करना!

छ- कारण उच्च न्यायालयों द्वारा न्यायिक समीक्षा की प्रक्रिया को सुविधाजनक बनाते हैं।

ज- कानून और संवैधानिक शासन के लिए प्रतिबद्ध सभी देशों में चल रही न्यायिक प्रवृत्ति प्रासंगिक तथ्यों के आधार पर तर्कपूर्ण निर्णयों के पक्ष में है। यह वस्तुतः न्यायिक निर्णय लेने का जीवन रक्त है जो इस सिद्धांत को उचित ठहराता है कि तर्क न्याय की आत्मा है। आई. इन दिनों न्यायिक या यहां तक कि अर्ध-न्यायिक राय उतनी ही अलग हो सकती है जितनी कि उन्हें देने वाले न्यायाधीश और अधिकारी। ये सभी निर्णय एक सामान्य उद्देश्य की पूर्ति करते हैं जो यह दर्शाता है कि प्रासंगिक कारकों पर निष्पक्ष रूप से विचार किया गया है। न्याय वितरण प्रणाली में वादियों के विश्वास को बनाए रखने के लिए यह महत्वपूर्ण है। जे. न्यायिक जवाबदेही और पारदर्शिता दोनों के लिए तर्क पर जोर देना एक आवश्यकता है। यदि कोई न्यायाधीश या अर्ध-न्यायिक प्राधिकारी अपनी निर्णय लेने की प्रक्रिया के बारे में पर्याप्त स्पष्ट नहीं है, तो यह जानना असंभव है कि क्या निर्णय लेने वाला व्यक्ति पूर्ववर्ती के सिद्धांत या वृद्धिवाद के सिद्धांतों के प्रति वफादार है या नही।

l. निर्णयों के समर्थन में कारण ठोस, स्पष्ट और संक्षिप्त होने चाहिए। कारणों का ढोंग या 'रबर-स्टैम्प कारणों' को एक वैध निर्णय लेने की प्रक्रिया के बराबर नहीं माना जाना चाहिए।

एम. इसमें संदेह नहीं किया जा सकता है कि पारदर्शिता न्यायिक शक्तियों के दुरुपयोग पर प्रतिबंध लगाने की अनिवार्य शर्त है। निर्णय लेने में पारदर्शिता न केवल न्यायाधीशों और निर्णय निर्माताओं को त्रुटियों के प्रति कम संवेदनशील बनाती है, बल्कि उन्हें व्यापक जांच के अधीन भी बनाती है। (डेविड शापिरो को न्यायिक सपष्ट वादिता के बचाव क्षेत्र देखे (1987) 100 हार्वर्ड लॉ रिव्यू 731-737 में देखें।

एन- चूंकि कारणों को दर्ज करने की आवश्यकता निर्णय लेने में निष्पक्षता के व्यापक सिद्धांत से उत्पन्न होती है, इसलिए उक्त आवश्यकता अब वस्तुतः मानवाधिकारों का एक घटक है और इसे स्ट्रासबर्ग न्यायशास्त्र का हिस्सा माना जाता था। देखें (1994)

19 ई. एच. आर. आर. 553,562 पैरा 29 और अन्या बनाम ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय, 2001 ई. डब्ल्यू. सी. ए. सी. आई. वी. 405, जिसमें अदालत ने मानवाधिकारों के यूरोपीय सम्मेलन के अनुच्छेद 6 का उल्लेख किया, जिसके लिए आवश्यक है, "न्यायिक निर्णयों के लिए पर्याप्त और बुद्धिमान कारण दिए जाने चाहिए।"

ओ- सभी सामान्य कानून क्षेत्राधिकार के फैसले भविष्य के लिए उदाहरण स्थापित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं।इसलिए, कानून के विकास के लिए, निर्णय के लिए कारण देने की आवश्यकता सार गार्भत है और वस्तुतः "उचित प्रक्रिया" का एक हिस्सा है।

(22) ऐसी परिस्थितियों में, दुर्भाग्य से इसके बाद पुलिस महानिरीक्षक द्वारा दिनांक 23.04.2010 पर पारित अपीलीय आदेश भी उसी दोष से ग्रस्त है जिसमें अपील रद कर दी गई थी। विशिष्ट याचिका यह ली गई थी कि अनुशासनात्मक प्राधिकारी को इस निष्कर्ष पर पहुंचना था कि जांच अधिकारी के निष्कर्षों को संदेह से परे साबित किया जाये, जोकि नहीं किया गया था।

(23) इस प्रकार, पुलिस महानिदेशक द्वारा संशोधन में भी दुर्भावना को ठीक नहीं किया गया था, जिन्हें निर्णय लेने के लिए उकसाया गया था, क्योंकि 2012 के सी. डब्ल्यू. पी. संख्या.23339 को 27.11.2012 पर इस निर्देश के साथ निपटाया गया था कि संशोधन पर 2 महीने की अवधि के भीतर तय किया जाए। पुलिस महानिदेशक ने केवल 1955 के नियमों के नियम 29 (डी) के तहत संशोधन की शक्तियों के मुद्दे पर विचार करते हुए 07.05.2013 पर संशोधन को खारिज कर दिया। आदेश का प्रासंगिक भाषा इस प्रकार हैः-

"07. मैंने सं. 015234644 पूर्व-सीटी/जीडी कमलजीत सिंह 84 बटालियन द्वारा प्रस्तुत याचिका का अध्ययन कर लिया है । सी. आर. पी. एफ. और डी. ई. के अन्य संबंधित अभिलेखों की बारीकी से जांच की गई और अभिलेख पर मामले की जांच की गई। याचिकाकर्ता द्वारा दलील दी गई कि निर्धारित प्रक्रिया का पर्याप्त अवसरों के साथ पालन नहीं किया गया है, उसे प्रदान नहीं किया गया है और उसी आरोप पर डी-नोवो पूछताछ नियमों का पूर्ण उल्लंघन है और केवल मामले को छिपाने और प्रमाणित करने के लिए मान्य नहीं है, जांच के दौरान, पी9 टी (एस. आई. सी. याचिकाकर्ता) को अपना बचाव करने का पर्याप्त अवसर दिया गया था और डी. ई. निर्धारित निर्देशों/प्रक्रिया के अनुसार आयोजित किया गया था। इससे पहले श्री सुरिंदर कुमार, 2-1-सी द्वारा प्रस्तुत डी. ई. कार्यवाही को कुछ प्रक्रियात्मक कमियों के कारण रद्द कर दिया गया था और डी-नोवो

जांच के लिए जारी आदेश काफी क्रम में और स्थापित मानदंडों के अनुसार था, जो किसी भी पूर्व निर्धारित और पक्षपातपूर्ण रवैये से बाहर नहीं था जैसा कि याचिकाकर्ता द्वारा आरोप लगाया गया था। इसके अलावा, याचिकाकर्ता द्वारा एक अन्य याचिका में कहा गया है कि वर्तमान मामले में, सी. आर. पी. एफ. नियम, 1955 के नियम 28 के तहत दी गई याचिकाकर्ता की अपील पर विचार करते समय पुनरीक्षण की शक्ति का प्रयोग किया गया है और सी. आर. पी. एफ. अधिनियम और नियम किसी व्यक्ति की अपील पर विचार करते हुए वरिष्ठ प्राधिकारी द्वारा सजा बढ़ाने पर विचार नहीं करते हैं, डी. आई. जी. अनुशासनात्मक प्राधिकरण यानी सी. आर. पी. एफ. नियम, 1955 के नियम, 29 (डी) के तहत कमांडेंट द्वारा दी गई सजा की समीक्षा करने के लिए सक्षम प्राधिकारी है। तत्काल मामले में, अनुशासनात्मक प्राधिआदेशण यानी कमांडेंट 84 बटालियन को याचिकाकर्ता को दिए गए संचयी प्रभाव के साथ तीन साल के लिए वेतन वृद्धि रोकने की सजा अपीलकर्ता द्वारा किए गए अपराध की गंभीरता के अनुरूप नहीं पाई गई और इसलिए इसे बढ़ाया गया और अपीलकर्ता पर डी. आई. जी., सी. आर. पी. एफ., चंडीगढ़ द्वारा सेवा से बर्खास्तगी की सजा लगाई गई। R.XIII-84/2009-EC-3 दिनांक 15/6/2009 अनुशासनात्मक प्राधिकरण द्वारा दी गई "संचयी प्रभाव के साथ तीन साल के लिए वेतन वृद्धि पर रोक" की सजा को रद्द कर दिया गया था। इस प्रकार कार्रवाई करें। डी. आई. जी. चंडीगढ़ रेंज द्वारा लिया गया समीक्षा प्राधिकरण निर्धारित प्रक्रिया/निर्देशों के अनुसार है।

08. मामले के सभी तथ्यों की पहले ही जांच की जा चुकी थी और विचार के लिए कोई योग्यता नहीं पाई गई थी।चूंकि याचिकाकर्ता द्वारा कोई नया तथ्य सामने नहीं लाया गया है, इसलिए मुझे पहले लिए गए निर्णय में हस्तक्षेप करने का कोई कारण नहीं मिलता है और इसलिए उसकी याचिका रद कर दी जाती है।"

(24) इस प्रकार, यह स्पष्ट होगा कि पुनरीक्षण प्राधिकरण भी उन कारणों को ध्यान में रखने में विफल रहा, जिन्होंने संचयी प्रभाव के साथ तीन वार्षिक वेतन वृद्धि को रोकने का आदेश लागू करते हुए अनुशासनात्मक प्राधिकरण को परेशान किया था।

(25) यद्यपि हम भारत संघ के वकील से सहमत हैं कि पुनरीक्षण की शक्तियों का प्रयोग अपीलीय प्राधिकरण द्वारा किया जा सकता था, यद्यपि वर्तमान मामले में विलंबित चरण में किया गया है, हमारी सुविचारित राय है कि विद्वान एकल न्यायाधीश द्वारा दिए गए कारण कि उक्त शक्ति

उपलब्ध नहीं थी, नियम 29 (डी) के प्रावधानों को देखते हुए टिकाऊ नहीं माना जा सकता है जैसा कि ऊपर पुनः प्रस्तुत किया गया है।

(26) हालांकि, अन्यथा दिये गये कारणों से हमारी सुविचारित राय है कि आपेक्षित आदेश दिनांक 15.06.2009 विधिवत रूप से कमांडेट द्वारा 01.08.2009 को सूचित किया गया! 15.06.2009 का विवादित आदेश, अपील को खारिज करना उचित नहीं था और इसे कायम नहीं रखा जा सकता है। इसी तरह, दिनांक 23.04.2010 (अनुलग्नक पी-12) 07.05.2013 (अनुलग्नक पी-16) की अपील में बाद का आदेश भी न्यायिक जांच की कसौटी पर खरा नहीं उतर सकता है और तदनुसार, हम यहां ऊपर देखे गए कारणों के लिए विद्वान एकल न्यायाधीश के आदेश में कोई गलती नहीं पाते हैं।

(27) परिणामस्वरूप, वर्तमान अपील को विद्वान एकल न्यायाधीश के आदेश के उपरोक्त संशोधन के साथ रद कर दिया जाता है, जिसे अधिकारियों द्वारा 3 महीने की अवधि के भीतर प्रतिवादी को बहाल करके लागू किया जाता है।

डॉ. पायल मेहता

अस्वीकरणः- स्थानीय भाषा मे अनुवादित निर्णय वादी के सीमित उपयोग के लिए है ताकि वह अपनी भाषा मे इसे समझ सके और किसी अन्य उद्येश्य के लिए इसका उपयोग नही किया जा सकता। सभी व्यवहारिक और अधिकारिक उद्येश्यों के लिए निर्णय का अंग्रेजी संस्करण प्रमाणित होगा और निष्पादन और कार्यान्वयन के उद्येश्य के लिए उपयुक्त रहेगा।

Translator (भाषा अनुवादक)

सीमा शर्मा

माननीय न्यायालय श्री सुदीप गोयल अतिरिक्त जिला स्तर न्यायधीश, यमुनानगर (जगाधरी)